अध्याय--१

बंगला देश का उदय

बीसवीं सदी के पांचवे दशक में ब्रितानी साम्राज्यवाद के शोषण से भारतीय उपमहाद्वीप मुक्त होकर स्वतंत्र हुआ. किन्तु यह 'स्वतंत्रता', जातीय भेद, धार्मिक संकीर्णता एवं राजनीतिक व शक्ति संघर्ष में परास्त एक वर्ग की हीन भावना के कारण मलिन हो गयी. भारतीय उपमहाद्वीप दो संप्रभुता संपन्न राजनीतिक इकाइयों में विभक्त हो गया. विभिन्न धर्मों, संप्रदायों एवं संस्कृति के मिश्रण से जनित उपमहाद्वीप का एकत्व भाव खंडित हो गया. 'भारत' एवं 'पाकिस्तान' दो राष्ट्र बने.

पाकिस्तान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य उपमहाद्वीप के मुसलमानों को जीवन में प्रगति के उन्नत अवसर प्रदान करना था. अतः स्वभावतः सीमित दृष्टिकोण लिए हुए पाकिस्तान 'इस्लामी' राष्ट्र बना. धार्मिक राज्य की स्थापना अवश्यक समझी गयी, अन्यथा पाकिस्तान की एक राजनीतिक इकाई के पक्ष में दिये गये तर्कों का कोई अस्तित्व ही न रहता. दूसरे, पश्चिमी पाकिस्तान के पास पूर्वी बंगाल को एक राष्ट्र के रूप में संबद्ध रखने के लिए धर्म के सिवाय अन्य आधार न था. इसी कारण से बहुत से विद्वान पाकिस्तान को एक राष्ट्र के रूप में नहीं मानते थे. प्रोफेसर मारगेन्थू ने लिखा है---'पाकिस्तान एक राष्ट्र नहीं है और राज्य बड़ी मुश्किल से. उसके पास इतिहास, नृजातीय मूल, भाषा, सभ्यता या उन लोगों की चेतना में जो उसकी जनसंख्या बनाते हैं कोई औचित्य नहीं है. उनके पास कोई समान हित नहीं है सिवाय हिन्दू प्रभुत्व के भय के. केवल इसी भय से, और किसी कारण नहीं, पाकिस्तान का अस्तित्व है.' [१]

पाकिस्तान के दो भाग न केवल १२०० मील के भारतीय भू-भाग द्वारा विभक्त थे बल्कि इससे भी अधिक वे भाषा, सभ्यता एवं व्यवहारिक असमानता के कारण राष्ट्र रूप में साथ रहते हुए भी पृथक थे. पश्चिमी पाकिस्तान में मध्यपूर्व के साथ तुलनात्मक दृष्टि से पूर्वी बंगाल की अपेक्षा अधिक समानता हो, जबकि पूर्वी बंगाल की सांस्कृतिक धरोहर संयुक्त बंगाल में उपजी. अतः स्वभावतः पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल के निकट है.

उपरोक्त असमानताओं के कारण पाकिस्तान के बनते ही आंतरिक विग्रह प्रारम्भ हो गया. इसका प्रस्फुटन सर्वप्रथम भाषा विवाद को लेकर हुआ. मोहम्मद अली जिन्ना ने

१: हॅस जे. मारगेन्थू 'मिलिटरी इल्यूजन', द न्यू रिपब्लिक, मार्च १६, १६५६ पृष्ठ सं० १४-१६, बंगला देश डाक्यूमेन्ट पृष्ठ ४ से लिया गया.

ढाका में भाषण देते हुए उर्दू को पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा घोषित किया, जिसका बहुत विरोध हुआ. पश्चिमी पाकिस्तान के शासक वर्ग द्वारा जनसंख्या के ३.३ प्रतिशत लोगों की भाषा उर्दू को पूर्वी बंगाल के लोगों पर थोपा जबकि १९५१ की जनगणना के अनुसार पूर्वी बंगाल के केवल १.१ प्रतिशत लोग उर्दू जानते थे. पूर्वी बंगाल की जनभाषा को दबाने का कार्य शासत्रीय स्तर पर अभी कुछ दिनों पूर्व तक होता रहा. फरवरी १९५२ में केंद्रीय सरकार द्वारा बंगला भाषा को फारसी लिपि में लिखे जाने का कुचक्र चलाया गया जो विफल रहा. उसके बाद पश्चिमी पाकिस्तान के दो पत्रों द पाकिस्तान इकानामिस्ट एवं वीकली मेल ने अपने दो अंकों में ५ एवं ११ जून व ४ एवं १० जून में क्रमश: पाकिस्तान की एकता की वकालत करते हुए बंगला लिपि (जिसको उन्होंने संस्कृत लिपि बताया) को अरबी या फारसी लिपि से बदला जाना आवश्यक बताया. पत्र के विचारानुसार 'संस्कृत लिपि' का उपयोग पूर्वी बंगाल के पश्चिमी पाकिस्तान से दूर होने का एक कारण है.[3] भाषा विवाद ने उग्र प्रांतीयता की भावना को जन्म दिया. पाकिस्तान की कठिनाइयां और बढ़ती गयीं क्योंकि भाषा-नीति की प्रतिक्रिया स्वरूप पाकिस्तान के शासक थोथी अस्मिता में उलझते गये और वे एक देशव्यापी विचारधारा की खोज में असफल रहे. 'इस्लाम' के भंगुर आवरण के बावजूद मतभेद उग्रतर होते गये क्योंकि पूर्वी बंगाल के लोगों को अवसर की समानता से वंचित रखा जा रहा था. अयूब खां ने १९५४ में लिखा कि पूर्वी बंगाल के लोगों में अभी तक हेय जातियों की विशेषताएं हैं एवं वे अभी तक अपने को मानसिक रूप से नवजात स्वतंत्रता की आवश्यकताओं के अनुरूप ढाल नहीं पाये हैं. एक लेखक के अनुसार-- संविधान प्रारूप कपोतकोष्ठ में फेंक दिया गया क्योंकि वह प्रांतीय दुश्मनी न सुलझा सका. प्रत्येक नीति एवं प्रत्येक कार्यक्रम की कसौटी थी. उस नीति एवं कार्यक्रम का अपने प्रांत पर प्रभाव. प्रांतीय आधार पर विकास योजनाओं के हेतु अर्थव्यवस्था की मांग बढ़ने लगी. फलत: पूर्वी बंगाल में चुनी गयी सभा ने पूर्ण प्रांतीय स्वायत्तता की मांग की.[4] -- कोई भी राजनीतिक परिवर्तन जो आर्थिक दुर्दशा को जन्म देता है ज्यादा नहीं टिक सकता, फिर चाहे जितनी मानवीय भावना ही उसके स्थापन का मूल कारण क्यों न हो. इसलिए यह अस्वाभाविक नहीं है कि पूर्वी बंगाल के लोगों की भावना की प्रकृति बदल गयी. पूर्वी बंगाल के हिंदू एवं

२: कुछ बाथ इन बंगला देश, प्रबोध चंद्र, पृष्ठ--६६.

३: कोओटेड फ्राम जरनल आफ इंस्टीट्यूट आफ डीफेंस स्टडीज एंड एनलेसिस, न्यूज रिव्यू आन पाकिस्तान, जून, १९७१, पेज ३८, पैरा-११६.

४: शिशिर गुप्ता, पालिटिकल ट्रेंड्स इन पाकिस्तान, फारेन अफेयर्स रिपोर्ट, दिसंबर १९५६, खंड-४, पेज-१३, ग्रंथ स०५

मुसलमानों की धार्मिक शत्रुता (जो बंगाल में १९४६ एवं ४७ के अलावा नहीं रही) के स्वभावत प्रांतीय शत्रुता का रूप (दूसरे पाकिस्तानियों से) ले लिया.[५] एक अन्य लेखक ने पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा पूर्वी बंगाल के शोषण को साम्राज्यवादी बताया है. साम्राज्यवाद को परिभाषित करते हुए वे लिखते हैं कि, 'यह एक ऐसा प्रभुत्व तंत्र है जिसमें दुर्बल का सबल द्वारा शोषण किया जाता है. अधिकांश स्थितियों में शोषण बहुविमीय होता है एवं यह राजनैतिक, आर्थिक, सैनिक, सांस्कृतिक एवं अन्य तत्वों से बना होता है..... साम्राज्यवादी संबंध ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय इकाइयों के मध्य ही देखे एवं समझे जाते रहे हैं.. पिछले वर्षों से इस साम्राज्यवादी शोषण संबंध ने अपने को एक दूसरे स्तर पर प्रकट किया है--वह है अंतरराज्यीय स्तर. उनके अनुसार इस अंतरराज्यीय शोषण को 'अंतर राज्यीय साम्राज्यवाद' कहा जा सकता है.'[६] यह अंतरराज्यीय साम्राज्यवाद तीन स्तर (राजनैतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक) पर प्रकट हुआ, और ये ही तीन वे प्रमुख कारण हैं जो 'बंगला देश' के उदय के कारण बने.

आर्थिक शोषण : पश्चिमी पाकिस्तान के शोषकों ने २३ वर्षों तक पूर्वी बंगाल का अनवरत शोषण किया. शोषण के अनंत आयाम थे. शुद्ध आर्थिक, सामाजिक आर्थिक, सैनिक, शैक्षणिक, ऐसा कोई क्षेत्र न था जो शोषण मुक्त हो. यह एक ऐसा सत्य था जो प्रत्येक बंगाली अपनी मज्जा के अंतरतम तक अनुभव कर चुका था. इस सत्य की अभिव्यक्ति विभिन्न अवसरों पर व्यक्त असंतोष के मध्य देखी जा सकती है. पूर्वी बंगाल में आए तूफान एवं बाढ़ से लाखों मनुष्य जन अपनी जान से हाथ धो बैठे. असहायता की स्थिति में शेख मुजीब ने कहा-- २३ वर्षों तक राष्ट्र में सहयोग के उपरांत भी हमारे पास बाढ़ नियंत्रण की कोई योजना नहीं है. पिछले दस वर्षों से बाढ़ नियंत्रण की योजना ही बन रही है. विशालकाय योजनाओं के मध्य बाढ़ नियंत्रण योजना दफन हो गयी. दस वर्षों में तूफान निरोधक शरणस्थल के लिए २० करोड़ रुपए नहीं जुट पाए जबकि पश्चिमी पाकिस्तान में मंगला और तरबेला बांधों के लिए १ अरब डालर की व्यवस्था बड़ी आसानी से हो गयी.[७] शेख मुजीब ने एक बार कहा था--'२०० वर्षों तक उपनिवेशवादी

५: वही. पेज १३८

६: के.पी. मित्र, इंटर स्टेट इम्पेरियलिज्म(विथ रिफरेंस टु ईस्ट पाकिस्तान) पेज २ और ३.. पेपर सबमिटेड टु द फिफ्थ जनरल कानफरेंस आफ इंटरनेशन पीस रिसर्च एसोसिएशन हेल्ड इन केन्डे (२२ टु २५ अक्टूबर १९७१)

७: मार्निंग न्यूज, करांची और ढाका--नवंबर २७, १९७०. कोटेड फ्राम बंगला देश डाक्यूमेंट, पेज १२२.

ब्रिटिश शासन भी लोगों का इस सीमा तक शोषण नहीं कर सका जितना चुनौती रहित शोषण, देश के इस भाग का (पूर्वी बंगाल), निहित स्वार्थों वाले पश्चिमी पाकिस्तान ने पिछले तेईस वर्षों में किया है.[८]

विभिन्न क्षेत्रों में असमानता निम्नलिखित तालिकाओं में देखी जा सकती है. तालिका में दिये गये अंक स्वयं ही पूरी स्थिति को उजागर कर देते हैं. वे किसी विश्लेषण के मोहताज नहीं हैं. ९

पूर्वी बंगाल का सशस्त्र सेनाओं में प्रतिनिधित्व

(१)	आफीसर	थल सेना प्राधिकृत	वास्तविक
(२)	जे.सी. ओ.	प्रतिशत नहीं	५ प्रतिशत
(३)	~~[illegible]~~ ओ. आर.एस.	७.८ प्रतिशत	७.४ प्रतिशत
		७.८ प्रतिशत	७.४ प्रतिशत
(१)	आफीसर	वायुसेना.	
	वारंट आफीसर	..	१६ प्रतिशत
	दूसरे पद	::	१७ प्रतिशत
		जल सेना	३० प्रतिशत
(१)	आफीसर	..	१० प्रतिशत
(२)	ब्रांच आफीसर	..	५ प्रतिशत
(३)	चीफ पेटी आफीसर	::	१०.४ प्रतिशत
(४)	पेटी आफीसर		१७.३ प्रतिशत
(५)	मुख्य सीमैन एवं निम्न	..	२८.८ प्रतिशत

८: ~~मार्निंग न्यूज़, कराँची~~ शेख मुजीबुर रहमान, डान (कराँची), २४ अक्टूबर, १९७१ कोवोटेड फ्राम पेपर सबमिटेड टु द फोर्थ जनरल कानफरेंस आफ एस.पी.आर.ए. बाई श्री के.पी. मिश्र.

९: नेशनल असेंबली आफ पाकिस्तान, डिबेट्स, ८ मार्च १९६३, पृष्ठ संख्या--२९-३१. कोवोटेड फ्राम पेपर सबमिटेड बाई के. पी.मिश्र ऐट आई.पी.आर.ए (२३अक्तूबर एण्ड २५ अक्तूबर ७१) पेज १३.

१०

नागरिक सेवाओं में पूर्वी पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व

वर्ष	सेवा का नाम	पूर्वी पाकिस्तान	पश्चिमी पाक.
१९६८	सिविल सर्विस आफ पाकिस्तान	१८६	३२६
१९६७	पाकिस्तान टेक्सेशन सर्विस	८६	१४१
१९६६	पाकिस्तान कस्टम एण्ड एक्साइज़ सर्विस	४०	७६
१९६५	पाकिस्तान रेलवेज एकाउंट सर्विस	२०	३६
१९६४	पाकिस्तान आडिट एण्ड एकाउंट सर्विस	४४	६५
१९६३	पाकिस्तान मिलिटरी एकाउंट सर्विस	१८	५०
१९६२	पोलिस सर्विस आफ पाकिस्तान	८२	१२८
१९६१	सेंट्रल इनफरमेशन सर्विस	१६	४६

११

विकास योजनाओं हेतु कोष का विनियोजन प्रतिशत

	पश्चिमी पाक	पूर्वी पाकिस्तान
विभिन्न विकास कार्यों हेतु विदेशी मुद्रा	८०	२०
विदेशी मदद(संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा दी गयी मदद छोड़कर)	६६	४
संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा दी गयी मदद	६६	३४
पाकिस्तान औद्योगिक विकास निगम	५८	४२
पाकिस्तान औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम	८०	२०
औद्योगिक विकास बैंक	७६	२४
भवन निर्माण	८८	१२
कुल जोड़:	७७	२३

१०: पाकिस्तान आब्ज़र्वर (ढाका), १६ जून, १९६६.
कोआटेड फ्राम पेपर सबमिटेड बाई के.पी. मिश्र ऐट आई.पी.आर.ए कानफरेंस (२२ अक्टूबर ७१) पेज़ १४.

पाकिस्तान के कुल निर्यात का ५० प्रतिशत से ज्यादा भाग पूर्वी बंगाल का होता था किन्तु इसके बाद भी निर्यात से होने वाली आय का पांचवां भाग ही पूर्वी बंगाल में खर्च किया गया. बाकी हिस्सा पश्चिमी पाकिस्तान में औद्योगिक सफाइयों में लगा दिया जाता था. और उनके उत्पादित वस्तुएं पूर्वी बंगाल में विक्रय की जाती थीं. आय के समान वितरण न होने से पूर्व की क्रय शक्ति घटती गयी. फलतः जीवन स्तर बहुत गिर गया. निम्न तालिका पूर्वी बंगाल के निर्यात एवं आयात का चित्र प्रस्तुत करती है.

पू पूर्वी बंगाल के विदेश व्यापार का मूल्य १९५०-६१ से १९६५-६६ तक
(रुपए, '000)

वर्ष	निर्यात	आयात	बढ़ा हुआ निर्यात आयात की तुलना में
१९५०-५१	१,२११,०७०	४५२,९३२	७५८,१३८
१९५१-५२	१,०८६,६२६	७६३,४५३	३२३,१७३
१९५२-५३	६४२,४७०	३६६,३५२	२७६,११८
१९५३-५४	७३९,६४५,०६८	२९३,७६०	३५१,३०८
१९५४-५५	७३१,५६९	३२०,२१७	४११,३५२
१९५५-५६	१,०४१,२९१	३६०,६८६	६८०,६०५
१९५६-५७	९०९,३७०	८१८,५३७	९०,८३३
१९५७-५८	९८८,०५८	७३५,६२४	२५२,४३४
१९५८-५९	७७८८०,९५४	५५३,७९७	३२७,१५७
१९५९-६०	१,०७९,५८४	६५५,२७५	४२४,३०९
१९६०-६१	१,२५९,९७९	१०४१,३८६	२४५,५९३
१९६१-६२	१,३००,५६०	८७२,८९२	४२७,७१८
१९६२-६३	१,२४९,२६४	१,०१८,६९२	२३०,५७२
१९६३-६४	१,२२४,१४०	१,४८८,५२१	२६४,३८१
१९६४-६५	१,२६८,१२८	१,७०१,८२३	४३३,६९५
१९६५-६६	१,५१४,२१८	१,३२८,०६२	१८६,१५६

आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए पूर्वी बंगाल के लोगों ने बहुत प्रयत्न किए. असफल रहने पर उन्होंने १९४० में लाहौर में पारित मुस्लिम लीग के प्रस्ताव के अनुसार पूर्ण प्रांतीय स्वायत्तता की मांग की. शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में अवामी लीग ने छह सूत्रीय कार्यक्रम दिया जिसमें मुख्यत: इस बात पर जोर दिया गया कि देश के दो भागों के लिए या तो भिन्न-भिन्न मुद्रा हो या दो अलग रिजर्व बैंक हों जिससे अंतरराज्यीय पूंजी के वितरण का न्यायिक नियमन हो सके. इस कार्यक्रम के अनुसार कर निर्धारण एवं एकत्रीकरण का अधिकार भी प्रांतों को मिलना चाहिए था.

पश्चिमी पाकिस्तान के लोग स्वभावत: उपरोक्त कार्यक्रम को स्वीकार नहीं कर सकते थे दूसरी ओर बंगाल इस शोषण को आखिर कब तक बर्दाश्त करता? अत: बंगला देश तो एक दिन बनना ही था. यही कारण था कि अंतत: बंगला देश को ६ स्वतंत्रता की घोषणा करनी पड़ी.

राजनैतिक शोषण :

१९५४ के प्रांतीय सभा के चुनाव में मुस्लिम लीग की भारी पराजय हुई. `युनाइटेड फ्रंट` की अवामी लीग के एच.एस सुहरावर्दी एवं कृषक श्रमिक पार्टी के श्री फजलुल हक के नेतृत्व में सरकार बनी. `युनाइटेड फ्रंट` ने एक निश्चित कार्यक्रम के आधार पर चुनाव लड़ा था. यह २१ सूत्रीय कार्यक्रम था जिसके मुख्य पक्ष निम्नलिखित थे.

(१) बंगला भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया जाए.

(२) संविधान सभा भंग की जाए एवं उसकी जगह प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर सभा चुनी जाए.

(३) पूर्वी बंगाल को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की जाए. मुद्रा, विदेश विभाग एवं प्रतिरक्षा को छोड़कर.

(४) जूट निर्यात के संबंध में केंद्र से स्वतंत्रता.

(५) विदेशी मुद्रा के विनियोजन में केंद्र और पूर्वी बंगाल में बातचीत.

(६) भारत एवं पाकिस्तान के मध्य पारपत्र एवं अनुवेशिका व्यवस्था की समाप्ति.

(७) पाकिस्तानी रुपए का अवमूल्यन.

'युनाइटेड फ्रंट' की इन मांगों में काफी बल था. बंगला भाषा को राजकीय भाषा घोषित की जाने की मांग स्वयं सिद्ध है. दूसरी मांग, जो संविधान सभा को भंग करके एक नयी संविधान सभा चुनने की थी काफी औचित्य रखती है. वह संविधान सभा १९४६ में सीमित मताधिकार के आधार पर चुनी गयी थी, एवं वह अपने कार्य को पूर्ण करने में असफल सिद्ध हो चुकी थी. पूर्वी बंगाल के लोग 'वयस्क मताधिकार' के अनुसार चुनाव चाहते थे अगर ऐसा होता तो वे जनसंख्या के आधार पर संविधान सभा में अपने बहुमत के द्वारा इच्छित संविधान बनाते. ऐसा संविधान जो उनको आर्थिक शोषण से मुक्ति दिलाता. संविधान सभा भंग कर दी गयी लेकिन युनाइटेड फ्रंट की विजय से नहीं बल्कि इसलिए कि उसने गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद की शक्ति में कमी करने का प्रयास किया था.

पूर्ण प्रांतीय स्वायत्ता की मांग शक्तिशाली केंद्र के प्रांतीय शोषण से मुक्ति पाने के लिए की गयी थी. १९३५ के एक्ट के कारण केंद्र बहुत शक्तिशाली हो गया था. दूसरे, स्वायत्ता की मांग १९४० में लाहौर में मुस्लिम लीग द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुकूल थी.

विदेशी मुद्रा के विनियोजन में केंद्र और पूर्वी बंगाल में बातचीत की मांग इस तथ्य की ओर इंगित करती है कि १९५४ तक केंद्र और पूर्वी बंगाल में कोई इस प्रश्न पर मंत्रणा नहीं होती थी. विदेशी मुद्रा का विनियोजन हमेशा पूर्वी बंगाल के विरुद्ध होता रहा. अतः स्वभावतः पूर्वी बंगाल के लोग पश्चिम के केंद्रीय अधिकार के विवेक में विश्वास खो बैठे.

भारत के साथ पारपत्र की समाप्ति की मांग में आर्थिक एवं सांस्कृतिक समस्याएं निहित थीं. पूर्वी बंगाल को पारपत्र के कारण काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था. वह तीन ओर भारत से एवं चौथी ओर बंगाल की खाड़ी से बंधा हुआ है. अतः एक तरह से वह विश्व से कट गया था.

युनाइटेड फ्रंट की उपरोक्त मांगों से खिन्न एवं चुनाव में उसकी विजय से अप्रसन्न पश्चिमी पाकिस्तानियों ने बंगालियों को विद्रोही की संज्ञा से विभूषित किया. पश्चिमी पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा बनावटी कागड़े करवाये गये. फजलुल हक एवं उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों को बातचीत हेतु कराची बुलवाया गया. बातचीत ३० मई १९५४ को समाप्त हुई. फजलुल और उन के साथी हवाई जहाज द्वारा वापसी यात्रा हेतु रवाना हुए. अभी उनकी यात्रा समाप्त भी नहीं हुई थी कि गवर्नर जनरल ने आपातकालीन स्थिति के आधारपर गवर्नर का शासन लागू कर दिया. फजलुल हक के कराची छोड़ने से पहले ही कि सिकंदर मिर्जा गवर्नर का पदभार संभालने जा चुके थे. इस प्रकार पाकिस्तान का इतिहास पूर्वी बंगाल के लोगों के साथ अनादर का इतिहास है.

१९५९ में प्रस्तावित आम चुनाव किसी न किसी भाँति टाला जा रहा था, अब तक अयूब खाँ प्रेसीडेंट बन चुके थे, उन्होंने मार्शल ला लागू कर दिया, १९६० में बढ़ते हुए जनमत के दबाव में उन्होंने प्रजातंत्र को फिर से स्थापित करने की घोषणा की, लेकिन उनका प्रजातंत्र अनोखा था, जो 'नियंत्रित' प्रजातंत्र कहा गया, उसके बाद वे 'बेसिक डेमोक्रेसी' पर आए, यह एक चतुराई मिश्रित दुरभिसंधि थी, इसके अनुसार पूरे पाकिस्तान में केवल ८०००० मतदाता बनाये गये, इनमें अधिकांशत: ~~कब्रपोशी~~ जन थे जो स्वभावत: केंद्रीय अधिकार के पक्षधर हो गये फलत: जन असंतोष उग्रतर हो गया, अयूब खाँ ने नेताओं के साथ चर्चा करके प्रत्यक्ष चुनाव करवाने का आश्वासन दिया, अपने प्रजातंत्र प्रेम एवं जन के साथ न्याय भावना को प्रतिपादित किया, उन्होंने,शेख मुजीबुर रहमान को जेल से मुक्त करके, किन्तु इन सब का कुछ भी लाभ नहीं हुआ, क्योंकि सेना प्रमुख याह्या खाँ, अयूब को हटा कर प्रेसीडेंट बन बैठे,

याह्या खाँ भी अपने पूर्ववर्ती शासकों से भिन्न न निकले, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, अपने २६ मार्च १९६९ के भाषण में उन्होंने कहा कि उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, वे संवैधानिक सरकार की स्थापना चाहते हैं, उन्होंने वायदा किया कि वे वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनीगयी सभा को शासन सौंप देंगे,

२८ मार्च १९७० को याह्या खाँ ने लीगल फ्रेमवर्क आर्डर निकाला, लीगल फ्रेमवर्क आर्डर में पाँच मूलभूत सिद्धांत भविष्य में बनने वाले संविधान के लिए बनाये गये, इनमें प्रथम, इस्लामी विचारधारा के ~~अनु~~ अनुरुप संविधान की बात थी, दूसरे सिद्धांत के अनुसार संविधान विधेयक राष्ट्रीय सभा द्वारा पारित किये जाने के बाद प्रेसीडेंट के सम्मुख विचारार्थ रखा जायेगा, प्रेसीडेंट संविधान को केवल औपचारिक रूप से ही प्राधिकृत नहीं करेगा, वह उसे निरस्त भी कर सकता था, [११] इस प्रकार यह स्पष्ट है कि चुनावी परिणाम से नहीं बल्कि पाकिस्तान के सैनिक तानाशाहों की सम्मति से ही पाकिस्तान का संविधान संभव था,

लीगल फ्रेमवर्क आर्डर की शेख मुजीबुर रहमान ने तीव्र भर्त्सना की, उन्होंने कहा कि वे एल.एफ.ओ. की भर्त्सना करते हुए भी चुनाव में भाग ले रहे हैं क्योंकि वे इस आम चुनाव को छ:सूत्रीय कार्यक्रम पर आधारित क्षेत्रीय स्वायत्ता की माँग के संबंध में मतसंग्रह के रूप में मानते हैं,

---

११: टेक्स्ट आफ प्रेसीडेंट याह्या खाँ'स एड्रेस टु द नेशन (२८ मार्च ७०) बंगला देश डाक्यूमेंट्स गवर्नमेंट आफ इंडिया पब्लिकेशन, पेज-४७,

सभा को संबोधित करते हुए शेख ने कहा कि बंगाली लोगों को उनके अधिकारों से बहुत दिनों तक वंचित रखा गया है, और आगामी आम चुनाव में समय आ गया है कि वे लोग अपने अधिकारों को फिर से ले लेंगे या तो चुनाव द्वारा या संघर्ष द्वारा.[१२]

दिसंबर ७० में हुए आम चुनाव में अवामी लीग की शानदार विजय हुई. उसका राष्ट्रीय सभा में स्पष्ट बहुमत हो गया. किन्तु मुजीब की जीत से पश्चिमी पाकिस्तानियों को प्रसन्नता नहीं हुई. पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपने मन का ज़हर उगलते हुए कहा कि उनकी पार्टी के सहयोग के बिना न तो संविधान बनाया जा सकता है न ही केंद्र में सरकार चलायी जा सकती है. अपनी बात स्पष्ट करते हुए उन्होंने आगे कहा कि उनके दल को पंजाब एवं सिंध में भारी सफलता मिली है एवं केंद्र को वास्तविक शक्ति इन्हीं दो प्रांतों से प्राप्त होती है. इसलिए बिना पीपुल्स पार्टी के सहयोग के केंद्र में कोई भी सरकार कार्य नहीं कर सकती.[१३]

भुट्टो के इस वक्तव्य से पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं की एकछत्रवादी मनोवृत्ति की झलक मिलती है. उनके मस्तिष्क में पूर्वी पाकिस्तान का चित्र एक राष्ट्र के अंग के रूप में नहीं बल्कि उपनिवेश रूप था. भुट्टो के उपरोक्त वक्तव्य से क्षुब्ध अवामी लीग के महासचिव, ताजुद्दीन अहमद ने कहा कि पंजाब और सिंध अब ज्यादा दिन तक `शक्ति के गढ़` नहीं रह सकते. लोगों का प्रजातंत्रीय संघर्ष इन `शक्ति के गढ़ों` के विरुद्ध था. प्रजातंत्रीय व्यवस्था में किसी प्रांत विशेष का नहीं अपितु जनमत का महत्व होता है.[१४] भुट्टो के इस वक्तव्य के बाद वादविवाद का लंबा दौर शुरू हुआ. भुट्टो ने प्रजातंत्रीय व्यवस्था में बहुमत के महत्व को अस्वीकार करते हुए कहा कि बहुमत का बल ही सब कुछ नहीं है. अपनी सत्ता लोलुपता को उजागर करते हुए उन्होंने संयुक्त सरकार की स्थापना की इच्छा व्यक्त की.. उन के अनुसार अगर पश्चिमी जर्मनी में वाल्टर शील और विली ब्रांट संयुक्त सरकार बना सकते हैं तो पाकिस्तान में अवामी लीग उन की पार्टी के साथ ऐसा ही समझौता क्यों नहीं कर सकती?[१५]

१२: शेख`स स्पीच, पोल्स, ए रिफरेंडम आन आटोनामी. नागांव-अक्टूबर २५. कोओटेड फ्राम `बंगला देश डाक्यूमेंट`, मार्निंग न्यूज (करांची) पेज़ १०१ एण्ड ढाका २६ अक्टूबर७

१३: जुल्फिकार अली भुट्टो`स स्टेटमेंट इन लाहौर आन दिसंबर २०,१९७०. कोओटेड फ्राम बंगला देश डाक्यूमेंट, पेज़ १३२. द पाकिस्तान टाइम्स, लाहौर दिसंबर २१,१९६ १९७०.

१४: ताजुद्दीन अहमद`स रिजोयांडर टु भुट्टो`स स्टेटमेंट. पाकिस्तान आब्जरवर--दिसंबर २२, १९७०. कोओटेड फ्राम बंगला देश डाक्यूमेंट, पेज़-१३३.

१५: जुल्फिकार अली भुट्टो`स स्टेटमेंट आन दिसंबर २१,१९७०. द पाकिस्तान टाइम्स, २२ दिसंबर, १९७०. कोओटेड फ्राम बंगलादेश डाक्यूमेंट, पेज--१३४-१३५

भुट्टो के वक्तव्य से विचलित हुए बिना शेख मुजीबुर रहमान ने उच्चकोटि की राजनीतिमत्ता का परिचय दिया. उन्होंने कहा कि वे अवामी लीग का बहुमत होते हुए भी संविधान निर्माण में पश्चिमी पाकिस्तान का सहयोग चाहेंगे. किंतु उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि संविधान के आधारभूत नीतिविषयक प्रश्नों पर कोई भी समझौता संभव नहीं है. [१६]

इस बीच तनावपूर्ण वातावरण चलता रहा. शेख मुजीब एवं भुट्टो में तीन दिन तक वार्ता चली जो ३० जनवरी ७१ को समाप्त हुई. वार्ता का कुछ परिणाम न निकला. याह्या खां ने १३ फरवरी ७१ की आधिकारिक घोषणा में राष्ट्रीय सभा का अधिवेशन ३ मार्च ७१ को ढाका में बुलाने की बात कही. भुट्टो ने कहा कि उनका दल राष्ट्रीय सभा के अधिवेशन में भाग नहीं लेगा, क्योंकि उनके दल को अवामी लीग का छह सूत्रीय कार्यक्रम मान्य न था. यद्यपि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि पूर्वी बंगाल के लोगों का बुरी तरह शोषण हुआ है. उन्होंने कहा कि उनके दल ने 'आंतरिक पूंजीवादी तंत्र को समाप्त करने पर बल भी दिया था. [१७] भुट्टो द्वारा राष्ट्रीय सभा के अधिवेशन को बहिष्कार करने की घोषणा की संपूर्ण पाकिस्तान में तीव्र आलोचना हुई. जमायते इस्लामी के अमीर मौलाना मदूदी ने संवैधानिक समस्याओं के हल को संविधान सभा के बाहर खोजने के निर्णय को अनुचित बताया. उन्होंने भय व्यक्त किया अगर सही दिशा में कदम नहीं उठाए गये तो देश का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है ऐसा ही भय पाकिस्तान नेशनल लीग के प्रधान अताउर रहमान ने भी व्यक्त किया. [१८] इन सब बातों का केंद्रीय सरकार पर कोई असर नहीं हुआ. प्रेसीडेंट याह्या खां ने भुट्टो की बातों में आकर ३ मार्च ७१ को होने वाले राष्ट्रीय सभा के अधिवेशन को स्थगित कर दिया. अधिवेशन के स्थगन का तीव्र असर हुआ. ढाका के पूरबानी होटल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए शेख मुजीब ने कहा कि २३ वर्षों के उपनिवेशवादी व्यवहार को समाप्त करने के लिए संयुक्त लड़ाई लड़ी जायेगी. उन्होंने चेतावनी भरे स्वर में कहा कि अगर षड्यंत्रकारियों के दिमाग ठीक नहीं हुए तो आप इतिहास बनते हुए देखेंगे. [१९]

१६: मुजीब'स स्टेटमेंट इन ढाका आन ३ जनवरी १९७१. कोओटेड फ्राम बंगलादेश डाक्यूमेंट पेज १३७

१७: जुल्फिकार अली भुट्टो'स ~~[illegible]~~ डिक्लेरेशन इन पेशावर, फरवरी १५, १९७ कोओटेड फ्राम बंगला देश डाक्यूमेंट, पेज-१५५-१५६

१८: पाकिस्तान आब्जरवर--फरवरी १७, १९७१. कोओटेड फ्राम बंगलादेश डाक्यूमेंट, पेज-१६

१९: शेख मुजीब'स टाक्स विद करोसपोंडेंट्स एट होटल पूरबनी आन १ मार्च, १९७१. 'द पीपुल', ढाका, मार्च २, १९७१. कोओटेड फ्राम बंगलादेश डाक्यूमेंट्स, पेज-१८९-१९०

राष्ट्रीय सभा के स्थगन की घोषणा के साथ ही केंद्रीय सरकार ने ढाका में अपना दमन चक्र शुरू कर दिया. २ मार्च १९७१ को निहत्थे लोगों पर गोली चलायी गयी. शेख मुजीबुर रहमान ने इस दमन पर अपनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए हड़ताल का आवाहन किया. अपने ७ मार्च तक के कार्यक्रम की घोषणा करते हुए उन्होंने लोगों से अनुशासित रहने का निवेदन किया. इसी बीच प्रेसीडेंट याह्या खां ने ढाका में १० मार्च १९७१ को पाकिस्तान के विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक का प्रस्ताव रखा. मुजीब ने इस के जवाब में कहा कि सैनिक ताने-बाने में अस्त्रों की भाषा में बात करना एवं फिर इस तरह का निमंत्रण देना पाखंड है.

मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में हड़ताल पूर्णत: सफल रही. मार्शल ला अधिकारियों ने सेना को वापस बैरक में बुलवा लिया गया. पांच दिन की हड़ताल समाप्त हुई. ढाका में स्थिति सामान्य हो गयी. किंतु यह शांति आने वाले तूफान की सूचक थी.

प्रेसीडेंट याह्या खां ने टिक्का खां को एहसान की जगह गवर्नर नियुक्त किया. टिक्का खां पाकिस्तान में अपनी निर्दयता के लिए कुख्यात हैं. असंतोष बढ़ता देखकर याह्या खां ने २५ मार्च को नेशनल असेंबली की बैठक की घोषणा की. इसके जवाब में शेख मुजीबुर रहमान ने कहा कि मार्शल ला के रहते, एवं बिना शासन को हस्तांतरित किए राष्ट्रीय सभा के अधिवेशन को बुलाने का कोई औचित्य नहीं है. इस के बाद मुजीबुर रहमान ने ७ मार्च १०७१ के वक्तव्य में १० सूत्रीय कार्यक्रम दिया. कार्यक्रम के अनुसार कर अभियान चलाये रखने, उच्च न्यायालय, अन्य न्यायालय, सचिवालय, सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालयों में हड़ताल का निर्देश दिया. इस बीच भुट्टो अपना ही राग अलापते रहे, एवं पूर्वी बंगाल में असहयोग आंदोलन तीसरे सप्ताह में पहुंच गया. इस असहयोग आंदोलन की विशेषता, संपूर्ण जनता का सहयोग था. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से ले कर निम्नतम पद पर कार्य करने वाले कर्मचारी ने शेख मुजीब के आदेशों का पालनकिया. संभवत: गांधी के `असहयोग` अस्त्र का सफलतापूर्वक प्रयोग पहली बार बंगला देश में हुआ.

असंतोष, तनाव एवं सत्ता पिपासु लोगों के षडयंत्र के शिकार पूर्वी बंगाल के लोगों ए मुख्यत: उनके नेता मुजीबुररहमान ने दूसरी बार राजनीतिमत्ता का परिचय दिया जबकि उन्होंने ढाका में याह्या खां से बातचीत करते हुए, पश्चिमी पाक के किसी भी नेता से मिलने में सहमति व्यक्त की. उन्होंने आशावादिता का परिचय देते हुए कहा कि वे हमेशा सर्वोत्तम संभव हल की अपेक्षा रखते हैं एवं निकृष्टतम का मुकाबला करने को तैयार हैं. [20]

२०: शेख मुजीब`स प्रेस कानफरेंस आन मार्च १६, १९७१ ढाका. द डान(कराची) २० मार्च,७

इसी कारण प्रेसीडेंट याह्या खां एवं भुट्टो से मुजीब ने बातचीत की. किन्तु उनकी आशावादिता भैंस के आगे बीन बजाने जैसी रही. क्योंकि वे बातचीत नहीं उसका ढोंग कर रहे थे. यह बात उनके एक कथन से स्पष्ट हो जाती है जिसमें उन्होंने कहा था कि त्रिपक्षीय समझौता होना चाहिए--एक और प्रजातांत्रिक ढंग से चुनी गयी दो पार्टियों में और दूसरी ओर सैनिक शासन, जिसे सत्ता हस्तांतरित करनी है.[२१] स्वभावतः तीन दलों में समझौता होना मुश्किल था. याह्या खां एवं भुट्टो १५ मार्च से २५ मार्च तक बेतुकी बातों का नाटक करते रहे, और इसी बीच सेना का जमाव पूर्वी बंगाल में बढ़ता गया. २५ मार्च को सेना ने अधुनातन अस्त्रों की सहायता से निशस्त्र जनता पर कहर ढाना प्रारम्भ कर दिया. अब पूर्वी बंगाल के लोगों के पास शोषण से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय था 'स्वतंत्रता' की घोषणा. शेख मुजीब ने २७ मार्च १९७१ को गुप्त रेडियो केंद्र से बंगला देश के स्वतंत्र राज्य होने की घोषणा की.[२२] पाकिस्तानी अत्याचारियों का ईस्ट बंगाल रेजीमेंट, ईस्ट बंगाल रायफल्स एवं बंगाल के जाबाज युवा लोग बड़ी दृढ़ता से मुकाबला कर रहे थे. जनता के प्रतिनिधियों ने जन भावना का आदर करते हुए १० अप्रैल १९७१ को मुजीबनगर में स्वतंत्रता की औपचारिक घोषणा की. ताजुदीन अहमद कार्यकारी प्रधानमंत्री बने.

इसके बाद का इतिहास लूट, हत्या, बलात्कार का इतिहास है. किंतु बंगाल झुका नहीं. मुक्तिवाहिनी ने सीमित साधनों द्वारा अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया. पाकिस्तानी शासकों ने उस समस्या का उत्तरदायित्व भारतवर्ष पर लाद दिया जबकि भारत पूर्वी बंगाल के करीब १ करोड़ शरणार्थियों का भार उठा रहा था. इस सहयोग पर भारत का आभार मानना तो दूर, उल्टे उल्टे पाकिस्तान ने अपनी बनायी समस्या से मुक्ति पाने के लिए भारत पर आक्रमण कर दिया, ताकि दुनिया का एवं पश्चिमी पाकिस्तान की जनता का ध्यान पूर्वी बंगाल में हो रहे हत्याकांड से हट जाए. भारत ने अपनी प्रभुसत्ता एवं अखंडता की रक्षा की एवं बंगला देश की मुक्तिवाहिनी के साथ सहयोग कर बंगला देश की धरती पर पाकिस्तानी अत्याचारियों को समर्पण के लिए विवश कर दिया.

२१: जुल्फिकार अली भुट्टो'स प्रेस कानफरेंस आन मार्च २२, १९७१ (ढाका). द डान(कराची) मार्च २३, १९७१. कोवोटेड फ्राम बी.डी.डी. पेज--२६०

२२: प्रेस रिपोर्ट २७ मार्च, १९७१. कोवोटेड फ्राम बंगला देश डाक्यूमेंट, पेज़-२८०